[Placed in Library. See No. LT-7495/95]

III. A copy (in English and Hindi) of the Annual Report and Accounts of the Sagar Gramin Bank, Ultadanga (West Bengal), for the year 1992-93, together with the Audiors' Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. LT-7581/95]

REPORTS AND MINUTES OF THE STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND CHEMICALS

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Standing Committee on Petroleum and Chemicals:—

(i) Seventeenth Report on 'Demands for Grants (1995-96)' of the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Minutes of the Sittings of the Committee relating thereto.

(ii) Eighteenth Report on 'Demands for Grants (1995-96)' of the Ministry of Chemicals and Fertilisers (Deptt. of Fertilizers) and Minutes of the Sittings of the Committee relating thereto.

(iii) Nineteenth Report on 'Demands for Grants (1995-96) of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Deptt. of Chemicals and Petro-chemicals) and Minutes of the Sitting of the Committee relating thereto.

RE: WITHDRAWAL OF RAILWAY CONCESSIONS ADMISSIBLE TO SPORTS PERSONS

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) उपसभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान देश के खिलाड़ियों के संबंध में जो बहुत ही शोकिंग डवलपमेंट हुई है, उनके बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में खेलों का स्तर काफी निराशाजनक है और जब ओलम्पिक खेलों में हम लोग बिना कोई बोझ मंडल जीते हुए आते हैं तो सारे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। मैं इस समय उन सारे मामलों में नहीं जाना चाहता कि उसके क्या कारण हैं। परन्तु दो डवलपमेंट ऐसी है जो इसी साल हुई हैं और मैं चाहता हूं कि सदन उसका जरूर नोटिस ले। एक तो यह हुआ है कि पिछले साल स्पोर्ट का बजट 71.44 करोड़ था, उसको कम करके इस वर्ष 68.76 करोड़ कर दिया गया। तीन करोड़ रुपए खेलों में कम कर दिया गया। जबकि पिछले साल के बजाए बाकी सब मामलों में.... (**व्यवधान**)

उपसभापति : मल्होत्रा जी, आपने जो दिया है, अगर आप उस पर पोइंटेडली बोलेंगे तो असर होगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उसी पर आ रहा हूं। एक तो यह बड़ी भारी शोकिंग डवलपमेंट थी। परन्तु दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा महत्व का है, वह यह हुआ है कि रेलवे मिनिस्ट्री जो कुछ कंसेशन देती थी, उन कंसेशन को उन्होंने या तो पूरी तरह विदड्रा कर लिया या पहले से काफी कम कर दिया। उपसभापति महोदया, रेलवे के अंदर ऐसा नहीं था कि खिलाड़ियों को भी परमानेंट पास मिले हों। जब खिलाड़ी नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने जाते थे, उनको पहले फर्स्ट क्लास में 50 परसेंट की छूट थी। और जो सेकेंड क्लास था, उसमें भी 50 परसेंट की छूट थी परंतु इस साल पहली मार्च से रेलवे ने फर्स्ट क्लास का पूरा कंसेशन विदड्रा कर लिया 100 परसेंट यानि कोई कंसेशन नहीं फर्स्ट क्लास में और जो सेकेंड क्लास हैं, उस में 50 परसेंट से कम करके उसको 25 परसेंट कर दिया।

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मैडम : क्या रेलवे बजट डिसकस हो रहा है?

[ ] شری سید سبط رضی : ابھی نہیں ہو رہا ہے ریلوے پر ڈسکشن۔

उपसभापति : नहीं, नहीं। रेलवे बजट तो बाद में आएगा।

श्री सैयद सिब्ते रजी : अभी नहीं हो रहा है रेलवे पर डिसकशन?

[ ]Transliteration in Arabic Script.

شری ارجن سنگھ بھنڈاری: میڈم۔ کیا ریلوے بجٹ ڈسکس ہو رہا ہے۔

उपसभापति : नहीं, नहीं । अभी तो ये डिसकस हो रहा है कि withdrawal of railway concessions admissible to sportsmen, a very serious situation arising out of this.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपसभापति महोदया, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं ।

"The Mnistry of Railways has decided that the element of concession admissible to sportsmen under annexures one and two to rule 101 of the coaching tariff—

यह वह है कि जो सिर्फ नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं—

may be reduced from 50 per cent to 25 per cent in second class and sleeper class and the concession in the case of first class be discontinued This will take effect from 1.3.95. This is issued with the concurrence of the Finance Directorate, Ministry of Railways."

उपसभापति महोदया, सेकेंड ए०सी० में कोई कंसेशन नहीं, रेलवे में कोई कंसेशन नहीं । हिंदुस्तान के अंदर लाखों फ्रीडम फाइटर्स को हम पास देते हैं फ्री । हमारे जो अटेंडेंट हैं एम०पीज़० के, वे भी फर्स्ट क्लास में और सेकेंड ए०सी० में ट्रेवल कर सकते हैं परमानेंटली अपने खर्च पर । स्पोर्टस मिनिस्ट्री के सारे आफिशियल्स, सारे आफिशियल्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वे एअर में ट्रेवल करते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पर । उनके यहां के सारे ऑफिसर सेकेंड ए०सी० में सफर करते हैं और उसी में हिस्सा लेने के लिए जब वे जाते हैं नेशनल में, ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे पर जाते हैं और हमारे छोटे बच्चे या नेशनल सीनियर्स, हिंदुस्तान के नंबर एक के खिलाड़ी 90 करोड़ के, जब वे जाते हैं तो जो भी उनको पिछल 40–50 साल से मिला हुआ था कंसेशन All of a sudden it has been withdrawn.

इससे पहले इतना शॉकिंग विदड्रॉल किसी मिनिस्ट्री ने कभी नहीं किया स्पोर्टसमेन के साथ । क्या उनको फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए ? सेकेंड ए०सी० में जाना ही नहीं चाहिए ? कोई उनकी रिज़र्वेशन नहीं है उपसभापति महोदया और मैंने देखा है, नंबर एक का खिलाड़ी हिंदुस्तान का, वहां पर लटकते हुए ट्रैवल करता है या बाहर खड़ा होकर ट्रैवल करता है और अपने खर्चे पर उसमें जाता है । आप उनसे यह उम्मीद करते हैं और जब प्रधान मंत्री भाषण देते हैं या हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, उसमें कहा गया कि जो भी संभव होगा हम उनको देंगे । आपने हज़ारों धर्माचारियों को फ्री पास दिए हैं। आपने समाज-सेवकों के नाम पर हज़ारों को फ्री पास दे रखे हैं । ये तो फ्री नहीं मांग रहे हैं और सिर्फ एक बार नेशनल में जाने के लिए या इंटरनेशनल कंपीटीशन में जाने के लिए 50 परसेंट का कंसेशन, वह भी आपने 100 परसेंट विदड्रा कर लिया है । फर्स्ट क्लास को कोई कंसेशन नहीं रखा और सेकेंड क्लास में 50 का 25 परसेंट कर दिया जो कि वहां पर बिना रिज़र्वेशन के स्लीपर क्लास में . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभापति : मल्होत्रा जी . . .

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपसभापति महोदया, मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें कोई पोलिटिक्स का सवाल नहीं है । कांग्रेस पार्टी के इतने चेयरमैन हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन के । यह हिंदुस्तान के हज़ारों-लाखों खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मैं चाहूंगा कि सारे सदन को इसको पहले तो वापस लें और जो पहले कंसेशन था, उसको वापस करें । नंबर दो, इसके लिए रिज़र्वेशन में प्राइयॉरिटी रखें । नंबर तीन, सेकेंड ए०सी० में अगर आप 50 परसेंट का कंसेशन नहीं देना चाहते तो उसका चाहे डिफरेंस आप उनसे वसूल कर लें । पर वे सेकेंड ए०सी० में ट्रैवल ही नहीं कर सकते, यह जो बाधा है, इसको हटाएं और मैं समझता हूं कि सारे सदन को इस सवाल पर सहमति करनी चाहिए और इसको फौरी तौर पर विदड्रॉ करना चाहिए ।

[]Transliteration in Arabic Script.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, I support his special mention. He has raised a very valid point and we have to support it. We keep on saying that we do not perform well in the sports front, and we do not even extend elementary facilities to our sports people. This is the very least that the Government can do. I support Prof. Malhotra.

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं एक ओर विजय कुमार मल्होत्रा जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और दूसरी ओर मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रोन्ज मेडल देश के लिए लाता है, उसको सरकार की ओर से जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों और दूसरे लोगों को, समाजसेवकों को फ्री पास दिया जाता है, उनके लिए भी फ्री पास की व्यवस्था की जाए।

विपक्ष के नेता (श्री सिकंदर बख्त) : सदर साहिबा, मैंने यह पढ़ा है It is a very terse and a very arrogant circular. कोई मतलब नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया गया है। बदकिस्मती से यह कोई मौका नहीं है स्पोर्टस पर बहस करने का। लेकिन शायद एच०आर०डी० पर हाउस में डिसक्शन हो, फिर स्पोर्टस पर बहस की जा सकती है। हिन्दुस्तान में स्पोर्टस की जो जिल्लत की कैफियत है उसमें एक-एक छोटे-छोटे कदम को जोड़कर उसको एक खराब मोड़ पर पहुंचा दिया गया है। इस सर्कुलर का कोई मतलब नहीं है, कोई रीजन नहीं है। इज इट थॉरोली ऐरोगेट, इज इट थौ रोली डेफ। कोई मतलब ही नहीं है। यह बहुत ही तोहीन-आमेज है। ऐसा मालूम होता है कि बहुत ही पत्थर किस्म के लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो खिलाड़ियों की कीमत नहीं जानते हैं। ऐसे हालात में हिन्दुस्तान के खिलाड़ी अपने मकाम को कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं इसकी सख्त मज्जमत करता हूं और अपने बात को विजय कुमार मल्होत्रा जी की बात के साथ बावस्ता करता हूं कि यह जो कंसेशन विदड्रा किया है, इस कंसेशन को वापिस लिया जाए। बाकी और बहुत सारी बातें हैं जो विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कही हैं, तो उन बातों पर मुनासिब मौके पर विचार किया जाएगा।

[]شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ میں نے یہ پڑھا ہے۔

کوئی مطلب نہیں ہے کوئی ریزن نہیں دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ کوئی موقع نہیں ہے اسپورٹس پر بحث کرنے کا لیکن شاید اے۔آر۔ڈی۔ پر ہاؤس میں ڈسکشن ہو پھر اسپورٹس پر بحث کی جا سکتی ہے ہندوستان میں اسپورٹس کی جو ذلت کی کیفیت ہے اس میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے قدم کو جوڑ کر اس کو ایک خراب موڑ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سرکلر کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی ریزن نہیں ہے ازاٹ تھوروِلی ایروگٹ۔ ازاٹ تھاروِلی ڈیف۔ کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی توہین آمیز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی پتھر قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کھلاڑیوں کی قیمت نہیں جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہندوستان کے کھلاڑی اپنے مقام کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں اور میں اپنی بات کو وجے کمار ملہوترہ جی کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں کہ یہ جو کنسیشن وڈرا کیا ہے اس کنسیشن کو واپس لیا جائے۔ باقی اور بہت ساری باتیں ہیں جو وجے کمار ملہوترہ جی نے کہی ہیں تو ان باتوں پر مناسب موقع پر وچار کیا جائیگا۔

[]Transliteration in Arabic Script.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, far from providing new incentives which the House has been urging, it is shocking to note that a few concessions which are there are being withdrawn. Let this withdrawal be withdrawn immediately

श्री दिग्विजय सिंह : आल्वा जी खेल मंत्री रह चुकी हैं, वे सरकार की तरफ से इस बारे में आश्वासन दें ।

उपसभापति : यह रेलवे का मामला है ।

श्री दिग्विजय सिंह : वे खेल मंत्री रही हैं, खिलाड़ियों के साथ उनका रिश्ता रहा है ।

उपसभापति : खिलाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है यह बहुत गलत है । दुनियां के हर मुल्क में खिलाड़ियों की अहमियत समझी जाती है ।

The Government should think of providing a lot of training, facilities and everything they need. But I am really surprised, shocked and aggrieved that this has happened. We are going to discuss the Railway Budget and the Minister of Railways is going to come soon. Mr. Mallikarjun is here on behalf of the Railway Minister. Mr. Mallikarjun, please make a note of the point because, It concerns the Ministry of Railways. I would like the Members to raise this issue when we discuss the Railway Budget. This order should be withdrawn and more facilities should be given to the sportspersons. If they come back without doing well, we abuse them. But we have never realised what we are doing to them and how they are being treated. Mrs. Alva, you wanted to say something.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, you have already said what we wanted to say.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are the Minister. You also say something.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, all I say is that we have introduced a Prize Money Scheme and an amount of Rs. 5 lakhs, Rs. 3 lakhs and Rs. 1 lakh is being given to those who win gold medal, silver medal and bronze medal respectively. This scheme is in operation for the last many years and the prize money is given to those who bring medals in the international events such as Olympics, Asian Games, etc. We have also introduced a life-time pension scheme for outstanding sportsmen. If there is some problem in the Railways which is mentioned here, we shall certainly take up the matter with the Ministry. We do feel that those who bring credit to the country must be recognised and rewarded and I share the concern expressed by the hon. Members.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is not for winning. medals. It is for participation in the annual tournaments.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: This concession is availed of only once in a year or two. It is not a permanent concession. It is only to participate in national tournaments.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is not a recognition. It is a facility to help them improve their standards.

SHRIMATI MARGARET ALVA: That is why all I am saying is that if such a concession has been withdrawn, then we shall certainly take up the matter with the Railway Ministry that this should be restored because we have very few sportsmen. There is no reason why we should withdraw this concession.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sure if these minor facilities are not going to be given, then definitely they are not going to bring any medals from abroad and they will also not be able to avail themselves

of whatever scheme the Government has for them. We should train them to avail themselves of the facilities which you have provided for them.

SHRIMATI MARGARET ALVA. Madam, I would also like to point out that those who participate in the national tournaments do not pay on their own. The federations concerned pay for them and most of the money paid by the federations is reimbursed by the Government itself under the sports schemes. So, the federations fund it from out of the funds they receive from the Government. It is not that they are paying it from their own; even the concession, if it comes

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: They themselves pay the amount. I can bet on this. The Government does not give a single penny for them. They pay on their own.

SHRIMATI MARGARET ALVA. You come here, I will tell you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Anyway, if it is paid by the Government. *(Interruptions)*.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: It is not being paid by the Government... *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: It is a false statement altogether. They pay for themselves. Otherwise, where was the question of giving some concession? There was no question of a concession if the Government was paying for them.

उपसभापति: कोई भी देता हो, सवाल यहां नहीं देने का है । देते हैं, उसकी बात नहीं है । अब सवाल यह है कि जो फेसिलिटी थी, उसको विदड्रा किया है, उसको रिस्टोर करें चाहे वह प्राइवेट दे रहे हों या सरकार फंड कर रही हो क्योंकि सरकार ने अगर किसी फेडरेशन को पैसे दिये है, ऐलोकेट किये हैं तो रेलवे के किराये में नहीं जाने चाहियें । उनकी निंग के लिए जाने चाहियें

and the Railways should also contribute it.

RE: MINIMUM WAGES AND IMPLEMENTATION OF THE TRIPARTITE AGREEMENT

SHRI JIBON ROY (West Bengal): I wish to know through you, Madam, from the Government, especially from the Labour Minister and the Finance Minister, if they have settled between themselves to disperse the best of technicians, engineers and skilled workers from the public sector undertakings to the private sector and, thus, allow the public sector to wither away automatically, or, if they have any desire to fulfil the commitments that they have made to the trade unions and the officers for meeting their economic demands. Hon. Members in this august House know that the ceaseless denigration and the implementation of the Voluntary Retirement Scheme had its toll over the morale of the workers. Very recently, they have changed the Company Law allowing the multinationals and the private companies to raise their higher wage level to one lakh of rupees per months. Naturally, in such a situation if the Government does not fulfil its commitments, the workers, the engineers and the technicians will leave and desert the public sector undertakings. Madam Deputy Chairman, there was a commitment on the part of the Labour Minister to the trade unions. The trade unions demanded that what ever wages were given to the workers and the officers should be protected throughout the period of operation of the agreement by neutralising the rise in prices. Accordingly, a tripartite committee was constituted which recommended that instead of one slab of D.A. for the lowest level, there should be three or four different slabs on the lines the Central Pay Commission has for the Central Government employees. The Government accepted the recommendations two years ago. But still it has not been cleared. The Finance Ministry is sitting on the file.